

सफलता की कुंजी
 इंसान के अंदर जो समा जाए वह स्वाभिमान और जो इंसान के अंदर से बाहर छलक जाए व अभिमान

सच कहने की ताकत
जालंधर ब्रीज
 साप्ताहिक समाचार पत्र

अनमोल विचार
 सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। स्वयं पर विश्वास करो।
 -स्वामी विवेकानंद

JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-1 • 16 JANUARY TO 22 JANUARY 2020 • VOLUME-21 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNJIN/2019/77863

अपने आप तो हम कोई काम नहीं करते जो भी करते है कोर्ट की फटकार के बाद ही करते है



फुटओवर ब्रिज न होने के कारण मजबूरन लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे विभाग के प्रप्ट अधिकारी।



रिहाईशो इलाके के लोगों द्वारा सड़क पार करने के लिए अवैध तरीके से बनाया गया फुटओवर ब्रिज की तस्वीरें।



जालंधर से विजय कुमार की विलेन रिपोर्ट

जालंधर जेल इलाका का जेल अफसर विजय कुमार ने अपने रिपोर्ट में प्रमुख राजमार्ग पर गलत तरीके से दो राई पैदीमशीन और टू वहीलर कीकाल रोड ब्रॉडिंग को रोकने के लिए अवैध बुराई की गई जिसका असर आप को जालंधर पब्लिक रोड पर लग हो गिरने से जहलम हो जायेगा।

जिसने पिछले पंचनू लोक अदालत कानूनवादी को जेल इलाका जालंधर कानूनवादी राजमार्ग पर दो राई इलाकों को लेबर चिंट प्रकट की गई थी जिस पर उसने बहुत बंधन लेते हुए ठेका प्राप्त कंपनी की कड़ी फटकार लगाते हुए वह अदालत दिया कि जब तक ठेका प्राप्त कंपनी सड़क राजमार्ग पर चल रहे बाधियों को रोपटी के तिरपे अपने द्वारा को गई कुटीयों को दूर नहीं करती तो एक हफ्ते के लिए को रोड को बंद करती नहीं कर सकती पर अपनी ताकत के बलबूते पर विभाग द्वारा इस अदालत पर रहे तो सिका और इसके बाद हाईकोर्ट में एपीटिवेट दिया कि जो हर तरह से बाधियों को रोपटी के



कोर्ट की फटकार के बाद तलवाली प्रोविशनाल पुलिसिस्टी के बाहर वैजलल हाइवे द्वारा पैदल रोड ब्रॉडिंग को रोकने के लिए किए गए प्रबंध की तस्वीरें।



में वैजलल हाइवे का दर्ज दे दिया गया था और इसके रोपटी तरह साकार और प्रॉविट कालीनहाइवे द्वारा रिहायशी प्रोविट विभागत कर दिए गए परन्तु यहाँ लोगों की विररी से जान भी खिलवाव हो रहा है कोई यहाँ पर पैदल रोड ब्रॉडिंग या बाईकाल रोड ब्रॉडिंग को रोकने के लिए कोई गिरिने नहीं लगाने और जो भी कोई फुटओवर ब्रिज बनाये गये और जहाँ पर प्रोविजन दिए गये यहाँ पर सड़क के किनारे बना कर जंग लगने के लिए छोड़ दिया।

विभाग के प्रप्ट अफसरों का तो यह हाल है कि अपने आप तो कोई काम नहीं करते है जो भी करते है।

कोर्ट की फटकार के बाद ही करते है इसके विभाग यह सहीत देना चाहते है कि हमारे पास ना उठनी सीधा कोर्ट जाने और विभाग के खिलाफ जर्जित बाधिका रापर करो और अगर कानूनवादी को जब की तरह कोई सुनवाई करेगा तो फिर इन सक्का इन होग।

जालंधर में तो तालाब की मछलीयां है परन्तु समुंदर का मगरमछ तो लुधियाना का रहने वाला है अवैध इमारतों को बनवाने के सरगना पर पैनी नजर बनाये सरकार

जालंधर से विजय कुमार की विलेन रिपोर्ट

पंजाब देश के सच्चे राज्यों में से किसी समय रहने के लिये व्यापार करने के लिये और कृषि के मजदूरी में देश का परसंटीय और चरकत वाला राज्य जिन्हा जालंधर था परन्तु इस पंजाब को प्रप्ट अफसरों ने अपने चंद पैसों के लालच को बलबूते से जो उसकी कुदरती रूप से उसकी पैदा भूख को रोपी देश चहुँपाई कि इसकी प्रकृतिक सुबसूती को बरत कर कंजरीट का जंगल बना दिया। सिन्धोसाल में विदेशी कंपनियों का प्रभाव लग 1990 में पड़ा और यहाँ विदेशी कंपनियों ने बड़े उद्योगिक स्तर जैसे बहालपु, विल्ली में अपने पैर पैगारते शुरू किये जिसको सुखानू धीरे-धीरे छोटे राज्यों से होते हुए पंजाब तक भी पहुँच गई परन्तु इस खुदरा को बरन् में कुछ प्रप्ट अफसरों ने बदल दिया इसका मुल्य करण जब विदेशी कंपनियों द्वारा इन छोटे राज्यों में पैर पैगार करे तो रिचल स्टेट सेक्टर में तेजी का दौर आया उस दौरान प्रप्ट अफसरों ने कुछ प्रॉविट पाईमन्सों के साथ मिल कर अवैध बनावतियों, अवैध कमिसिनाल इमारतों का खेला शुरू किया और इस से शहर को कंजरीट के जंगल का रूप दे दिया और इस बीच की लाल चालते लुधियाना शहर से शुरू होने वाले जालंधर अनुत्तर तक के प्रप्ट अफसरों को भी लग गई। इन सभी अफसरों को पंजाब में जो फिटका के नाम से जाना जाने लगा जिसमें कुछ को अदालत करने अफसर से करोदगुनी बनकर रिहाय हो गये और कुछ को अदालत करने मजहूर प्रप्ट अफसर सेटीयट में तैनाती के बाद पूर्व विभाप मंत्री द्वारा दिग्गमिपन कर दिया गया पर इन सब के बाद इसका सरपन बन गया लुधियाना में रहने वाला एक प्रप्ट अफसर जिसे से पंजाब के लोकल बाडी विभाग में अवैध किल्लीगी बनवाने का केलाप चारहाह कहा जाता है। इस प्रप्ट अफसर को इसके साथी अफसर को पंजाब नहीं करके उसका कारण है कि किसी भी रिश्तत के लेन देने में यह किसी को भी शामिल नहीं करता और अपनी मज्जी और अपने हिस्साप से ही उनको उनका हिस्सा देता है अगर कोई अफसर उसके खिलाफ आवान खुलने करने की कोशिस करता है तो भी वह अपनी विजिलेंस विभाग में अफकी सीटिंग होने के कारण विजिलेंस से पकड़े बना कर उसकी रखा लेता है।



इस प्रप्ट अफसर को इसके साथी अफसर भी पंजाब नहीं करके उसका कारण है कि किसी भी रिश्तत के लेन देने में यह किसी को भी शामिल नहीं करता और अपनी मज्जी और अपने हिस्साप से ही उनको उनका हिस्सा देता है अगर कोई अफसर उसके खिलाफ आवान खुलने करने की कोशिस करता है तो भी वह अपनी विजिलेंस विभाग में अफकी सीटिंग होने के कारण विजिलेंस से पकड़े बना कर उसकी रखा लेता है।

कारण इसका नाम पंजाब में कपड़ों पार्थ में आया था परन्तु इस प्रप्ट अफसर ने अपने प्रप्टावर के पैसों से इसी पार्थ बना तो कि यह किसी भी चीज को कुछ पंटी में पैगिज कर लेता है इसके पीछे पंजाब के एक रसुखदार मंत्री का भी हाथ बताया जाता है अगर पंजाब में सरकार अवैध विजिलेंसों के खिलाफ सख्त है तो इसके सरगना के उतर पैनी नजर बनाने और इसके द्वारा जलाई जा रही अवैध इमारतों को उमारी को रोकने के लिए इसके नेकर ट्रेडिंग पर लगाने और सख्त इफट्टे करके इसके खिलाफ करपन एक्ट के अधीन इस पर मुकरमा चला कर ऐसे प्रप्ट अफसरों को सलाखों के पीछे भेजे और इसकी केनारी संरक्षित का पता लगा कर अपने कब्जे में लें।

निर्मया गैंगरेप: दोषियों को 22 जनवरी को फांसी मुश्किल दया याचिका पर फैसले के बाद मिलेगा 14 दिन का वक्त

नई दिल्ली/ ब्यूरो

निर्मया गैंगरेप केस में फांसी को वक्त पाए टोपी मुकेश कुमार ने टुवल कोर्ट के रिच खॉरि को रू कराने की मांग की है। उसकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता धीरज की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान दिल्ली एएसजी और दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। मुकेश को और से जर्जिज वकील विभापक जॉन ने कोर्ट में दलील दी कि 7 जनवरी को टुवल कोर्ट की ओर से चरित



जोरेत अभी तक तमिल नहीं हो सका है। अगर इन दिसेंबर के अदालत पर दया याचिका रापर करने के लिए 7 दिन का रोटील देते तो 25 दिसेंबर को यह सवाल हो जाता। लेकिन एजिकका को रोके से फिलाने को अनुमति 30 तरीक को दी गई।

बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को पांच जजों को पीठ ने मुकेश को चहुँदोप याचिका खरिपन कर दी थी। इसकीप, निर्भया की मां जलल देवी ने कहा कि लोके जो चाहे कर ले, लेकिन इस केस में सब कुछ सफा है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से कुछ रिचल नहीं है। उम्मीद है कि मुकेश को मंगल खरिपन होगे।

थल सेना प्रमुख ने पाक, चीन सीमाओं पर तैनात सैनिकों को हर समय सतर्क रहने को कहा

नई दिल्ली/ ब्यूरो

थल सेना प्रमुख जनरल एम एम शारंग ने चीन, पाक की सीमाओं पर तैनात और कश्मीर में लड़ युद्ध से मुकाबला कर रहे सैनिकों को चौबीस घंटे सतर्क रहने को कहा। इसके साथ उन्होंने जवानों को थरोस दिलाना कि उनकी विभिन्न पदकों की किर्मी भी कीमत पर घुट किया जाए। उन्होंने सेना दिवस को पूर्व संथा पर 13 लाख कर्मियों वाले बल को दिए अपने संबित में कहा कि भारतीय सेना ने राष्ट्र के मन में एक निरोध स्थापन कराया है और यह केवल एक लड़कुच संघटन या राष्ट्रीय शक्ति का औदार नहीं है।

उन्होंने कहा, यह देश को एक सुसज्जत संरक्षक भी है। हमें अपने सुल्लों, आचार और अपने नागरिकों द्वारा अलार पर भरोसे को बनए रखने के संकल्प में जुड़ बने रहना है। उन्होंने प्रमुख रक्षा अफसर (चीवीएस) के तहत सैन्य मामलों का विभाग बनने के संस्कार के फैसले की एक चालचपक कदम बताया जिससे सीमा सेनाओं के बीच अधिक सम्पन्न होया। बल सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना की प्राथमिक जिम्मेदारी सीमा सेना की विपरीतों परकरण रखता है। उन्होंने सभी कर्मियों, छात्राकर पाकिस्तान, चीन की सीमाओं और शिपचिन लोतिपर को रूठ कराने वाले जवानों, से कहा कि वे हर समय सतर्क रहें। उन्होंने लड़ा युद्ध को



जटिल पुरीतों का मुकाबला करने वाले जवानों को भी सतर्क करने को कहा, जनरल शारंग ने कहा कि इन यह सुनिश्चित करेगे कि अपनी परिपालन साठोसाठान संबंधी जकालों को हर कीमत पर घुट किया जाए, उन्होंने कहा कि सेना ने उपरोक्त खतरों से निपटने के लिए सिद्धांतिक अनुकूलन और क्षमता वृद्धि की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सैन्य मामलों के विभाग के शठन पर उन्होंने कहा कि इससे नाटकीय-सैन्य सल्लमल में वृद्धि होगी, एफएलिक परिचायों को उपाधकल बढ़ेगे और लोचें सेनाओं के बीच अधिक से अधिक सम्पन्न हो सकेगा।

दखल बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां



सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ पहलों में कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक इनके अंतिम परिणाम नजर नहीं आए हैं। वहीं बैंकिंग क्षेत्र को सहायक बनाने के लिए एक नई, कई सुधारक कदम उठाने की जरूरत बनी हुई है। पिछले साल अर्थव्यवस्था में जिस तरह मंदी की शुरुआत हुई, बैंक घोटाले हुए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बूटने का संकट गहराया, इन सब घटनाओं ने लोगों के मन में अर्थव्यवस्था को लेकर संदेह पैदा किया है। पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएचबी) के घोटाले से सहकारी बैंकों से भी आम जनता का भरोसा टूटा है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता के लिए सहकारी बैंकों (यूवीबी) के लिए चला देने की जरूरत को सलाह बनाने का प्रयास है। सरकारी के अनुसार बैंक अपने कुल जमा का अर्ध हिस्सा ही वित्तियों और स्मॉल को धरिण्य में खर्च के रूप में दे सकेंगे। इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल जमा में से कम से कम आधा जमा 25 लाख रुपय प्रति अकाउंट से अधिक नहीं होना चाहिए, उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के लिए जमा राशियों को बढ़ाना होगा।

ऐसे ही 31 फीसद बढ़ी है। आकाश वित्त कंपनी की हाइड्रोजन पेट्रोलिंग कंपनी (एचएफसी) पर नकारात्मक असर भी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त का विषय रहा है। मुख्य रूप से नौ बड़े अकाश वित्त कंपनियों इसकी श्रेणी में आई हैं, जिसकी परिणति का अंकास रिजर्व 2018 के 2.94 लाख करोड़ रुपय के मुकाबले 26 फीसद बढ़ कर वर्ष 2019 में 2.17 लाख करोड़ रुपय का रहा। भारत में कुल 103 एचएफसी हैं, जिसमें से सात ने परिचालन का लाइसेंस मिलने के बाद कारोबार शुरू नहीं किया है। परिचालन वाली 94 एचएफसी में से 76 को बैंको, एनएचबी और ब्यांकर से जवाब वित्तीय सहाय मिल है, वहीं 18 आरपी एचएफसी की उधारी 65 हजार 595 करोड़ रुपय घटी है। एक और बड़ी चिंता एचएफसी में गैर निवासी निवेशकों को खरी एचएफसी बढ़ने में जुड़ी है।

पिछले साल अर्थव्यवस्था में जिस तरह मंदी की शुरुआत हुई, बैंक घोटाले हुए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बूटने का संकट गहराया, इन सब घटनाओं ने लोगों के मन में अर्थव्यवस्था को लेकर संदेह पैदा किया है। पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले से सहकारी बैंकों से भी आम जनता का भरोसा टूटा है। सरकार सुधार के प्रयास कर रही है, असर भी दिखा है। उम्मीद है कि जल्द बैंकों में बदलाव की किरण नजर आएगी।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार एचएफसी क्षेत्र का सकल फंडा कार्ड (जीएनपीए) वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 6.1 फीसद पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2018 में 5.3 फीसद था। वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही से इसमें और गिरावट आई है, क्योंकि इस अवधि में जीएनपीए में घटौती बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा एचएफसी के मुनाफे में कमी बढ़ रही है कि इन कंपनियों के सामने संकट गभीर है। रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में एचएफसी के लाभ में कमी की मुख्य वजह जमा नहीं लेना रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट खोखापट्टी से जुड़े मामलों बढ़ने का रहा है। ग्लोबल वित्त बैंकों के बढ़ते से लेकर अकाश वित्त कंपनियों और एचएफसी तक में खोखापट्टी के कई मामलों सामने आए हैं। रिजर्व बैंक ने सालाना रिपोर्ट 'बैंकिंग क्षेत्र का रहस्य एवं प्रतीति' में कहा है कि खोखापट्टी के मामलों में 15 फीसद और इससे संबंधित खसम की मात्रा में 74 फीसद का इजाजत हुआ है। रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकिंग क्षेत्र में खोखापट्टी के 6801 मामलों दर्ज किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह आंकड़ा 5916 था। खोखापट्टी से संबंधित खसम सालाना अंकास पर 41 हजार 167 करोड़ रुपय की तुलना में बढ़ कर 71 हजार 543 करोड़ रुपय दर्ज की गई। रिजर्व बैंक के अनुसार बढ़ती दरत के घोटाले लंबे अलसल के बाद सामने आते हैं। इस वजह से बैंकों द्वारा दर्ज खोखापट्टी के मामलों की संख्या के साथ-साथ इसी संबंधित खसम में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान तेजी दर्ज की गई। इसमें परिचालन जर्जिधों के प्रथम में

असमंजस का पता चलता है। बैंक के मुनाफिक कुल खोखापट्टी मामलों में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की भारीदारी 30.7 फीसद और 11.2 फीसद रही, जबकि खोखापट्टी से संबंधित खसम में इनका योगदान 7.7 फीसद और 1.3 फीसद रहा। हालांकि हाल की बात यह है कि बैंकों के फंडे कार्ड में घटौती बोलत हुई है। रिजर्व बैंक का कहना है कि अर्थव्यवस्था में फंडे कार्ड में और बनी आरपी। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था सहित की वजह से इस का फंडे कार्ड की वजह से तेजी आई। बैंकिंग क्षेत्र का सकल एचएफसी अनुपात मार्च 2018 के 11.2 फीसद से घट कर मार्च 2019 9.1 फीसद रह गया। मौजूदा समय में वृद्धि में नयी और कार्ड उधार कम होने के साथ ही डिपॉजिट चूक के मामलों और खोखापट्टी की घटनाओं से बैंक कार्ड देने से शिथिल रहे हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि मुदा अधिक हलाकत और खसमों पर घेनुत अधिक गतिविधियों में नयी ने जर्जिध गहन करने की समता को प्रभावित किया है और उधारी की मात्रा कम हुई है। हालांकि परिणति की गुणवत्ता में सुधार और बैंकिंग क्षेत्र का मुनाफा सुदृढ़ता अर्थव्यवस्था में है और खसमों के खसम क्षेत्र के बैंको का पूर्वी अनुपात सकारात्मक बैंकिंग क्षेत्र में पूर्वी खलने से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में कम प्राधान्य की वजह से बकाय मुनाफे में बढ़ोतरी हुई। दिवालीय सहित होने के बवजूद एचएफसी की समस्या बनी है। बैंकों में खोखापट्टी की घटनाएं बढ़ने से उनकी मुक्ति को बढ़ी है। बैंकों को अभी न केवल निगमकीय खसमों को पूरा करने के लिए, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी पूर्वी को सहायक बनना है। खसम, रिजर्व बैंक द्वारा उधार देने वाले कर्जों से जारी सकारात्मक बैंको की कार्यप्रणाली व वित्तीय स्थिति में बेहोरी आने की संभावना है। रिजर्व बैंक के अनुसार सकारात्मक बैंको के मिलाप से अर्थव्यवस्था को भी सहायक होने की उम्मीद है। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली निश्चित करने व एचएफसी क्षेत्र को मजबूत करने से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। महामंडल में केड सकारा और रिजर्व बैंक, बैंको और एचएफसी में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण सुधारक कदम उठा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि नए स्तर में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है।

सतीश सिंह (विदुट पत्रकार)

विचार

शिक्षा संस्थानों की फिक्र करें

देश के 208 अकादमिक विद्वानों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि लेफ्ट विंग के लोग शिक्षा के माहौल को खराब कर रहे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर सामर्थ्य एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी हो, शैक्षिक संस्थानों में राजनीति बंद होनी चाहिए।



नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में भरे बवाल के बीच ऐसी अनिश्चितता की स्थिति बनती जा रही है, जिसमें यह कहना कठिन है कि कौन सही है और कौन गलत। अभी कुछ दिनों पहले देश के 100 से ज्यादा पूर्व नौकरवालों ने खुला पत्र लिखकर यह कहा था कि देश को सीएच व एनएचबी की जरूरत नहीं है। सरकार अतिरिक्त हलाकत को सुधारने पर ही ध्यान लगाए। नौकरवालों के इस पत्र को सरकार के विरोध के स्वरूप लिया गया था। अब देश के 208 अकादमिक विद्वानों ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि लेफ्ट विंग के लोग शिक्षा के माहौल को खराब कर रहे हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर सामर्थ्य एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाल में ही जेएनयू से जामिया और एएमयू से जायपुर युनिवर्सिटी तक में सामने आए घटनाक्रम से पता चलता है किन तरह से अकादमिक माहौल को खराब किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों और जेएनयू में हुई हिंसा के बाद लिखते हुए इस पत्र को अकादमिक जगत में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित माना जा रहा है।

अभी तक पत्र के मजबूत को देखें तो पत्र लिखने वाले लोगों में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्राध्यापक भी शामिल हैं। पत्र में लिखा गया है कि लेफ्ट विंग के एंटी-इंस्टीट्यूट की बगल में देश में अकादमिक माहौल को खराब करने में जुटी है। पत्र को लिखने वालों में हरि सिंह गैर युनिवर्सिटी के कुलपति आरपी विवाही, साउथ बिहार स्टेट युनिवर्सिटी के कुलपति एचएचएस राव और सरकार घटते युनिवर्सिटी के वीसी शशिष कुलकर्णी हैं। शिक्षण संस्थानों में लेफ्ट विंग की अराजकता के खिलाफ बखान शीर्षक से लिखे गए पत्र में कुल 208 अकादमिक विद्वानों के हस्ताक्षर हैं। शिक्षकों के इस पत्र के बाद देश में नए किस्म की बहस शुरू हो गई है। लेफ्ट विंग पर जिस तरह का निशाना साया गया है, वह बता रहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था ही समीक्षा करने की जरूरत है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य की धारणा इस तरह से बनने की जरूरत है, जिससे वह पढ़ने नए छात्र-छात्राओं को बेवजह के विवाद का शिकार न होना पड़े। इस तरह का माहौल बनाने के कई संकेत हैं। पहला तो यह कि शिक्षा संस्थानों में सरकार छात्र राजनीति पर सरकार रोक लगाए। विश्वविद्यालयों में चुनाव करने व नेतृगरी करने का मार्ग सरकार ने ही तैयार किया है। जब वह राजनीति खत्म होगी तो सब अपने-अपने ही ठीक हो जाएगा। दूसरे भी राजनीति करने के लिए पूरा देश फल है, बैंकों की संख्या में राजनीतिक दल है। जो जिस चाहे अपना सकता है। दूसरा संकेत यह हो सकता है कि कॉलेजों में आने वाले छात्रों को बंद प्रस्ताव जाए कि वे राजनीति नहीं करेंगे और ऐसी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिससे किसी समुदाय या धर्म को ठेक पहुंचे। इससे कुछ संकेत तो सही हैं। कैम्पस का राजनीति में घटौत का माहौल बना है, उसने शिक्षा के माहौल को ही बर्बाद किया है।

छात्र आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं

नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने देश में आत्महत्या के जो आंकड़े उजाह किए हैं, वे चिंताजनक हैं। किसी भी समाज और देश के लिए यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। कोई भी शख्स आत्महत्या को अंतिम विकल्प क्यों मान रहा है? नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आत्महत्या के मामलों में 3.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और औसतन देश में हर दो घंटे में तीन लोग जान दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में कुल एक लाख 34 हजार 516 लोगों ने खुदकुशी की, जो 2017 के एक लाख 29 हजार 887 आत्महत्या के मामलों के मुकाबले 3.6 फीसदी अधिक है। आत्महत्या के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र 17 हजार 972 में दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 13 हजार 896 है और तिसरे पर पश्चिम बंगाल 13 हजार 255 है। इसके बाद मध्य प्रदेश 11 हजार 775 और कर्नाटक 11 हजार 561 है।



विकल्प क्यों मान रहा है। एक और संकेत लक्षण यह सामने आया है कि बेरोजगारी से आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में किसानों से जवाब बेरोजगारी ने आत्महत्या की। 2018 में 12 हजार 936 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। इसी अवधि में कुल 10 हजार 349 किसानों आत्महत्या की। केरल में 1585, तमिलनाडु में 1579, महाराष्ट्र में 1260, कर्नाटक में 1094 और उत्तर प्रदेश में 902 लोगों ने बेरोजगारी की वजह आत्महत्या की। दूसरी ओर देश में किसानों की आत्महत्या का निश्चित रूप से बढ़ रहा है। खेती का संकट व्यापक है और इसकी श्रेणी में अनेक राज्यों के किसान आ रहे हैं। यह वजह है कि अधिक किसानों से अब तक केवल किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यह निश्चित रूप से बढ़ रहा है। 2018 में 10 हजार 349 किसानों ने आत्महत्या की है। दरअसल, अक्सर और आत्महत्याएं नए देश की महामारी के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। अक्सर इतिहास कई लोग आत्महत्या जैसे घटना घुस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल शिक्षा और अक्सर में पीड़ित घटना में ही हो। सबसे निश्चित देश अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक लोग अक्सर से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7.5 फीसद लोग किसी-किसी तरह के मानसिक अस्वास्थ्य से पीड़ित हैं, लेकिन भारत में अक्सर कोई बीमारी नहीं मान जाता और इसके इलाज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इलाज तो पूरा पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के बजाय लोग उसका खसम उठाते हैं। कई बार तो वे मानसिक रूप से असंतुलित रहित न मानता नता कर मां दिया जाता है। इसका मतलब है अक्सर मामलों सामने आते हैं। बीमारी का इलाज करने के बजाय पड़े-पड़े लोग भी खसम चूक के चक्कर में फंस जाते हैं।

इन पांच राज्यों में ही लगभग 51 फीसदी आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए। राजधानी दिल्ली में दो हजार 526 खुदकुशी के मामले दर्ज किए गए। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि देश में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2018 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि आत्महत्या को लेकर बेहद चिंताजनक तथ्य सामने आ रहा है। 2018 में लगभग 10 हजार 159 छात्रों ने जान दी है। इसमें से एक चौथाई ने इतिहास में फंस होने के डर से आत्महत्या की। प्रेम में जकड़ने, उन्मत्त-शिक्षा के मामले में अधिक समस्या, पोस्मोर्ट न मिलना और बेरोजगारी भी छात्रों की आत्महत्या की प्रमुख वजह के रूप में सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक एक दशक में लगभग 82 हजार छात्रों ने आत्महत्या जैसे अंतिक कदम उठाया है। महाराष्ट्र में 1448 छात्रों के आत्महत्या के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं।

नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में किसानों से ज्यादा बेरोजगारों ने आत्महत्या की। 2018 में 12 हजार 936 लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। इसी अवधि में कुल 10 हजार 349 किसानों ने आत्महत्या की। किसी भी समाज और देश के लिए यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। कोई भी शख्स आत्महत्या को आखिरी विकल्प क्यों मान रहा है? इस पर आज पूरे देश को मंथन करने की जरूरत है।

इसके बाद तमिलनाडु 953, मध्य प्रदेश 862, कर्नाटक 755 और पश्चिम बंगाल 609 से खसम आत्महत्या के मामलों सामने आ रहे हैं। छात्रों की आत्महत्या के 45 फीसदी मामले इसी पांच राज्यों में हैं। जब भी देश में कोई भी बहोत आते हैं और कई बच्चों के आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आती हैं। वे छात्रों खसम पर-खसम आ रही हैं। इस समस्या का कोई हल निकलना हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दरअसल, मौजूदा दौर की गलतफहम प्रतिस्पर्धा और माता-पिता की असीमित अपेक्षाओं के कारण बच्चों को जीवन में भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बेटों को और

धनुक लेती है। दूसरी ओर माता-पिता के साथ संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां बच्चे परिवार, स्कूल और कॉलेज में तरसना स्थिति नहीं कर पाते हैं और उनका बच निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। इसी वजह से उनके जीवन में अब निरर्थक पढ़ाई को ही खसम लेते हैं। सौ-सौ कसर मोबाइल ने पूरी कर दी है। दूसरी ओर माता-पिता के पास खसम ही नहीं है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। नौकरी व कारोबार की व्यस्तताएं हैं, उनका लक्षण है। जहां पर मां नौकरीवाले हैं, वहां संबंधों में तनाव और गंभीर है। एक और वजह है। भारत में परंपरागत संयुक्त परिवार का लक्षण घटता जा रहा है। परिवार एकाकी हो गए हैं और नए व्यवस्था में बच्चों को माया-दादी, चाचा-चाची का सहाय नहीं मिल पाता है, जबकि

बहिन बचक में उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही वजह है कि अनेक बच्चे आत्महत्या जैसे अंतिक कदम उठा लेते हैं। परीक्षा परिणामों के बाद हर साल अखबार पृष्ठों पर खसम लेते हैं। बेटों और सखीयनिक संकट हेतु लाइन चलते हैं, लेकिन छात्र-छात्राओं की आत्महत्या के मामले कम नहीं रहे हैं। जर्जर है कि वे प्रथम नकारात्मक हैं। बच्चे संघर्ष करने के बजाय हम मां का आत्महत्या का सहाय रसत घुस ले रहे हैं। माता-पिता और शिक्षकों की मह निम्नोदारी है कि वे लक्ष्य बनने को यह समझाए कि परिवार परिवार ही एक कुल नहीं है। ऐसे में कोई उदाहरण है कि जब इतिहास में बेहतर न करने वाले लोगों ने जीवन में सफलता के मुख्य हस्तित किए हैं। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है कि कोई बच्चा आत्महत्या को अंतिम

अनुसूतम वर्तुदी (विदुट पत्रकार)

जेलों में आधुनिकीकरण की शुरुआत

राष्ट्रीय अनाथ विद्यालयों (एनवीएल) की ताल रिपोर्ट के अनुसार देश में जेलों की संख्या से अधिक कैदियों की मौजूदगी समस्या बन गई है। मध्यप्रदेश ने जेलों की इस समस्या का निदान कर लिया है। सरकार ने 10 नए जेल बनाने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक केंद्रीय जेल इंडिया और सब जेल महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य एवं पूर्वी जेल सेवा सहित जिला जेल केरल, तमिलनाडु, राजगढ़, मुंबई और मद्रास में नए जेल बनाई जा रही हैं। राज सरकार ने जेलों में वीआईपी कैदियों के उपचार लक्ष्य है। अब जेल में ही कैदी कोर्ट कम से हाजिरी लाइसेंस अर्पण कर सकेंगे। इस व्यवस्था से कैदियों को कोर्ट ले जाने-लाने का खर्च बचाने और उनकी सुरक्षा की विले से भी सुविधा मिलेगी।

राज सरकार ने डिहवापुर में नए जेल कैम्पलेक्स (संयुक्त) के निर्माण के लिए करीब 225 करोड़ की लागत दी है। इससे प्रदेश में पहली बार एक ही संकुल में कैदीय जेल, जिला जेल तथा सुनई कैलोनो विगत होगी। इंडिया में नवी कैदीय जेल के निर्माण की भी वैश्वीकरण सहित हो गई है। सिविली जेल शुरू हो गयी है और बिना जेल का कार्य प्रगति पर है। कैदीय जेल भोजपार में मार्च-2019 को खुली जेल शुरू की गई। कैदीय जेल, महाराष्ट्र परिसर में 20 बंदियों के लिए स्थानी जेल के निर्माण के लिए

साथ दो करोड़ से अधिक को खसम खसम की गई है। सायाय योगा क्लब, चंद्रशेखरी, भोजपार स्थित प्रशिक्षण अकादमी में मार्च 2019 से 90 बंदियों को एक साथ का आहारपत्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्य-सत्य पर मुख्य प्रदी,प्रदी को एक दिवसीय अर्ध-प्रशिक्षण/प्रशिक्षण केंद्रों के जेल प्रबंधन शोध संस्थान, भोजपार में प्रेषित जा रहा है। जेलों के प्रभुओं का दो दिवसीय सम्मेलन पहली बार दिल्ली से बाहर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोजपार में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ संयुक्त रूप से किया गया। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के महानिदेशक, वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

राज सरकार ने प्रदेश की 37 कैदीय, जिला एवं सब जेलों में इं-डिजिटल बंधन शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा प्रेषित है इस कार्यक्रम के तहत कैदीय जेल कनेक्ट रूप उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम में बंदियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रदेश की सभी जेलों को राज्य सरकार ने संबंधित व्यापारकों से वीआईपी कैदियों के वाहन से जोड़ दिया है। कैदीय जेल भोजपार, जयपुर, उज्जैन, इंदौर एवं बड़ोदा में ही अंडर ग्राउंड प्रदी प्रदी प्रदी एवं ग्राउंड जेलों में 590 आधुनिक

